

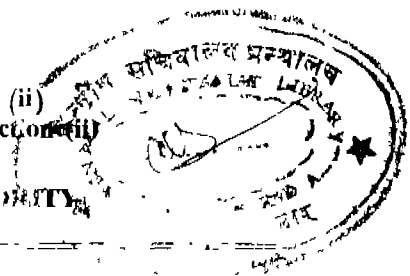


भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY



सं. 197] नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 31, 1993/चैत्र 10, 1915

No. 197] NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 31, 1993/CHAITRA 10, 1915

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a
separate compilation

उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 31 मार्च, 1993

का.आ. 219(अ)/18कक/आई.डी.आर.ए./93 :—भारत सरकार के उद्योग
मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश संख्या 320(अ)/18कक/आई.डी.आर.
ए./79 तारीख 26 मई, 1979 द्वारा (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त आदेश कहा

गया है) मैसूर अपाला जिप्स कपनी प्राइवेट लिमिटेड कलकत्ता नामक संपूर्ण औद्योगिक उपकरण का प्रबंध उद्योग (विकास और प्रिनियम) अधिनियम 1951 (1951 का 65) की धारा 18क की उपधारा (1) के खंड (ग) के अधीन 25 मई, 1982 तक की, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, तीन वर्ष की अवधि के लिये ग्रहण किया गया था और मविब, वन्द और उद्योग विभाग, पश्चिम बंगाल सरकार को, जिसे अब मविब, औद्योगिक पुनर्निर्माण विभाग, पश्चिम बंगाल सरकार कहा जाता है, उक्त औद्योगिक उपकरण का प्रबंध ग्रहण करने के लिये प्राधिकृत किया गया था।

और केन्द्रीय सरकार ने अपनी यह नीति लोचन में यह समीचीन है कि उक्त आदेश तीन वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्रभावी बना रहे, 31 मार्च, 1993 तक की, जिसे यह तारीख भी सम्मिलित है, और अवधि के लिये इसे जारी रखने के लिये समस्त-समय पर निर्देश जारी किये गये थे। (द्विपक्षीय भारत सरकार के उद्योग मन्त्रालय, औद्योगिक विकास विभाग के आदेश)

- स. का. प्रा. 246(ग)/18क/आई डी आर ए /82, तारीख 25 मई, 1982
 स. का. प्रा. 832(ग)/18क/आई डी आर ए /82, तारीख 24 नवम्बर 1982
 स. का. प्रा. 385(ग)/18क/आई डी आर ए /83 तारीख 31 मार्च, 1983
 स. का. प्रा. 872(ग)/18क/आई डी आर ए /83, तारीख 30 नवम्बर, 1983
 स. का. प्रा. 172 (ग)/18क/आई डी आर ए /84 तारीख 28 जन, 1984
 स. का. प्रा. 975(अ)/18क/आई डी आर ए /84, तारीख 29 दिसम्बर, 1984
 स. का. प्रा. 275(अ)/18क/आई डी आर ए /85 तारीख 29 मार्च, 1985
 स. का. प्रा. 146(ग)/18क/आई डी आर ए /85, तारीख 31 मार्च, 1986
 स. का. प्रा. 216(ग)/18क/आई डी आर ए /87, तारीख 30 मार्च 1987
 स. का. प्रा. 316(ग)/18क/आई डी आर ए /88, तारीख 30 मार्च, 1988
 स. का. प्रा. 217(अ)/18क/आई डी आर ए /89, तारीख 31 मार्च, 1989
 स. का. प्रा. 277(ग)/18क/आई डी आर ए /90, तारीख 30 मार्च, 1990
 स. का. प्रा. 214(ग)/18क/आई डी आर ए /91, तारीख 26 मार्च, 1991 और
 स. का. प्रा. 250(अ)/18क/आई डी आर ए /92, तारीख 30 मार्च, 1992

और केन्द्रीय सरकार की यह नीति लोचन में यह समीचीन है कि उक्त आदेश 31 मार्च, 1994 तक की, जिसे यह तारीख भी सम्मिलित है, और अवधि के लिये प्रभावी बना रहे।

अनः केन्द्रीय सरकार उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18क की उपधारा (2) के परन्तुक के साथ पठित धारा 18कक की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह निर्देश देता है कि उक्त आदेश 31 मार्च, 1994 तक की, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है और अवधि के लिये प्रभावी बन रहेगा।

[फा.सं. 2/23/80-सी.यू.एस./आई.आर.एस.]

अखण्ड प्रताप सिंह, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Industrial Development)

ORDER

New Delhi, the 31st March, 1993

S.O. 219(E)|18AA|IDRA|93.—Whereas by the order of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) No. S.O. 320(E)|18AA|IDRA|79, dated the 26th May, 1979 (hereinafter referred to as the said order), the management of the whole of the industrial undertaking known as Messrs. Apollo Zipper Company Private Limited, Calcutta was taken over under clause (a) of Sub-section (1) of Section 18AA of the Industries (Development & Regulation) Act, 1951 (65 of 1951) for a period of three years upto and inclusive of the 25th May, 1982 and the Secretary, Closed and Sick Industries Department, Government of West Bengal, now called Secretary, Industrial Reconstruction Department, Government of West Bengal, was authorised to take over the management of the said Industrial Undertaking.

And, whereas, the Central Government being of opinion that it is expedient in the public interest that the said order should continue to have effect after the expiry of the period of three years aforesaid, had issued directions from time to time, for such continuance for a further period upto and inclusive of the 31st March, 1993 (Vide Orders of the Government of India in the Ministry of Industry, Department of Industrial Development).

- Nos. S.O. 246(E)|18AA|IDRA|82, dated the 25th May, 1982,
 S.O. 832(E)|18AA|IDRA|82, dated the 24th November, 1982,
 S.O. 385(E)|18AA|IDRA|82, dated the 31st March, 1983,
 S.O. 872(E)|18AA|IDRA|83, dated the 30th November, 1983,
 S.O. 472(E)|18AA|IDRA|84, dated the 28th June, 1984,
 S.O. 975(E)|18AA|IDRA|84, dated the 29th December, 1984,

S.O. 275(E)|18AA|IDRA|85, dated the 29th March, 1985,
S.O. 146(E)|18AA|IDRA|86, dated the 31st March, 1986,
S.O. 266(E)|18AA|IDRA|87, dated the 30th March, 1987,
S.O. 326(E)|18AA|IDRA|88, dated the 30th March, 1988,
S.O. 247(E)|18AA|IDRA|89, dated the 31st March, 1989,
S.O. 277(E)|18AA|IDRA|90, dated the 30th March, 1990,
S.O. 214(E)|18AA|IDRA|91, dated the 26th March, 1991, and
S.O. 250(E)|18AA|IDRA|92, dated the 30th March, 1992.

And whereas, the Central Government is of the opinion that it is expedient in the public interest that the said order should continue to have effect for a period upto and inclusive of 31st March, 1994.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-section (2) of Section 18AA read with the proviso to Sub-section (2) of Section 18A of the Industries (Development & Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby directs that the said order shall continue to have effect for further period upto and inclusive of the 31st March, 1994.

[F. No. 2(23)|80-CUS|IRS|

A. P. SINGH, Jt. Secy.